[Shri P. Rajgopal Naidu]

Ambassadors' Offices and there is so much of sabotage in the country. Many people suspect that this is also a sabotage.

Government has not given the details with regard to the recent fire accidents. Government has also not said anything about the help given to the families of victims, whether compensation was given or not. It is creating a scare in the country. Unless Government takes stern measures to put down all this violence it will create confusion in the country. Therefore, I request the government to investigate into the matter and let the House know about the details.

(v) FAILURE TO GIVE CITIZENSHIP RIGHTS TO REFUGEES WHO CAME TO INDIA AFTER 1971 INDO-PAK WAR

श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज उस समस्या को लेना चाहता हूं जिस का समाधान आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था यह समस्या क्षेत्रीय नहीं है, किन्तु एक राष्ट्रीय समस्या है। 1971 में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के समय सिन्ध और गुजरात की सीमा पर रहने वाले जो लोग थे उन्होंने हमारी सेना को रास्ता बताया। मैं उन सब गांवों को देख कर आया हूं, उस समय जब हमारी सेना पाकिस्तान पर आक्रमण करने जा रही थी तो उन्हें रास्ते का पता नहीं था कि कौन से रास्ते से जा कर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। पाकिस्तान के अन्दर रहने वाले उन व्यक्तियों ने उसे रास्ते बताये जिस के कारण हमारी भारत की सेना पाकिस्तान को परास्त करने में सफल हो गई। परिणाम यह हुआ कि हमारा जो समझौता हुआ उस समझौते में जब हम उस क्षेत्र को खाली कर के यहां आए तो क्यों कि उन्होंने भारत की सेना को रास्ता बताया था इसलिए अगर वे पाकिस्तान में रह जाते तो दो बातें उन के साथ होतीं—या तो उनका जीवन पशु-तुल्य होता या वे मौत के घाट उतार दिए जाते, इसलिए वे हिन्दुस्तान में चले आए। उन की संख्या लगभग आधा लाख है। आज उनकी दशा अत्यंत दयनीय है। मुझे आश्चर्य होता है कि बंगला देश के बन्धियों के रहने के लिए देवरी कैम्प में और अन्य स्थानों में पक्के मकान थे, लेकिन उन के लिए एक तम्बू नहीं, एक टेन्ट नहीं और हमारे मंत्रालय ने गत वर्ष उनको आवास के लिए 2 सौ रुपये दिए। क्या दो सौ रुपये में कोई मकान बन सकता है ? 200 रुपये में तो कोई घास का छप्पर भी नहीं बन पाता है। जैसे तैसे कर के उन्होंने जो झोपड़ी बनायी वह आग लगने के कारण जल कर खाक हो गई। अब आज उन के रहने के लिए कोई मकान नहीं है। खाने के लिए उन्हें तीस रुपये मिलते हैं और बालकों को 15 रुपये मिलते हैं। तीस रुपये में आज की महंगाई के जमाने में क्या कोई जीवन का निर्वाह कर सकता है। उन बच्चों को पूरा राशन मिले, वह भी नहीं होता। केवल 30 रुपये उनको मिलते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि आज उन में से कोई शरणार्थियों के कैम्प में अध्यापक के पद पर लग गया तो गत 6 वर्ष में दी हुई सबसिडी उस से रिकवर हो रही है। वह कहां से देंगे ? उन के पास खाने के लिए पैसा नहीं और उनसे रिकवरी के आर्डर चले गए। हम ने कई पत्र लिखे मंत्रालय को कि कम से कम रिकवरी तो बन्द कर दी जाय। मुझे आपसे यह कहना है कि आखिर इनका क्या अपराध है, क्या दोष है ? इन का अपराध तो यही था कि जो हमारी भारत की सेना वहां आक्रमण करने के लिए गई उसे उन्होंने रास्ता बताया और यही नहीं, भारत सरकार का जिस में कोई पैसा नहीं लगता, एक नागरिकता का अधिकार भी उन को वह नहीं दे सकती। पुरानी सरकार तो कह रही थी कि इन को वापस भेजेंगे। हमारी उन के साथ बातचीत चल रही है। कैसे ये वापस जाएंगे। जाएंगे तो मौत के घाट उतारे जाएंगे। अगर उन्हें नागरिकता का अधिकार होता तो उन में कई ऐडवोकेट्स हैं, कई पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्हें नौकरी मिल सकती थी या वे कोई धन्धा कर सकते थे। आज वे पशु तुल्य जीवन तो नहीं बिताते। यह समस्या बहुत बड़ी है। मैं ने इसलिए

इस के ऊपर कालिंग अटेंशन दिया था। आज उन के मरने जीने का प्रश्न है। उन के लिए दवाइयां नहीं, पढ़ने के लिए किताब नहीं, ओढ़ने को कम्बल नहीं, रहने को मकान नहीं, कुछ भी उन के पास नहीं। ऐसी परिस्थिति के अन्दर क्या भारत सरकार केवल 200 रुपये साल में उनको मकान के लिए देकर शांत बैठ जायेगी ? मैं निवेदन करूंगा कि सरकार उन के आवास को, उन के एजुकेशन की व्यवस्था करे और शीघ्रातिशीघ्र रिकवरी बन्द कर। मैं जानता हूं केवल एक मंत्री महोदय का यह काम नहीं हो सकता। सारा मंत्रिमंडल बैठकर इस के ऊपर जल्दी निश्चय करे और निश्चय कर के उन्हें नागरिकता का अधिकार दे दे ताकि वे पशुवत जीवन न बिता कर भारत के अन्य नागरिकों की तरह अपने पुरुषार्थ से पूंजी कमा सकें और दयनीय दशा में न रहें।

(iv) SALE OF SEVERAL THOUSAND EAST PAKISTAN REFUGEE WOMEN FROM MANA CAMP

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : Sir, I want to draw the attention of the House through you to a very shocking and at the same time shameful affair that has been reported to the Chief Minister of West Bengal by a delegation of MLAs who were sent to Mana camp, Deoli camp and other different camps where the former East Pakistan refugees have been rotting for periods ranging from 7 to 15 years. Recently a group of MLAs was sent there to see the condition of the refugees in those camps. On the 17th, they and also 17 members of those refugee camps have made a representation to the Chief Minister of West Bengal wherein they have said that about 10,000 girls and women have been taken away from the Mana camp and other camps also and sold outside.

SHRI SHYAM NANDAN MISHRA (Begusarai) : What are the authorities doing ?

SHRI SAMAR GUHA : There are serious complaints against the authorities. The girls and women have been subjected to shameful behaviour. There are reports against the police also that some of the girls were taken away and atrocities committed on them. You will remember, I raised this matter of the rotting conditions in which the refugees life in different camps for 7 to 15 years. 1,30,000 former East Pakistan refugees have been kept by the Government deliberately in Mana and other camps, from where it is very difficult for them to come here and get any information whatsoever. They cannot come to the cities and make complaints. All kinds of reports against the employees and some other agencies are also coming again and again. The Minister for Rehabilitation is not here. I want to make a humble sggestion through you to the Minister that he may make a statement on this matter. The report has come out in Ananda Bazar Patrika of 18th December and it has been submitted by responsible persons who visited the camps. I would humbly request the minister to enquire into the matter about the behaviour meted out, by the government employees and also many other agencies working there to the refugees who have been kept in Mana camp, Deoli camp and other camps in Dandakaranya. An enquiry should be made and a report presented here. The conditions in which the refugees are living are almost at a sub-human level. A team of Members of Parliament should visit these refugee camps and make a report to the Government about their condition and also the policy in regard to their rehabilitation. These refugees who met the Chief Minister of West Bengal made an appeal that they want to go to Andamans. The other day when I raised the matter, the minister said, they will not be sent to Andamans. Almost every session I have been bringing this matter to the attention of the House. The Government promised that they will be sent to Andamans, but the Minister said the other day that they will not be sent to Andamans. The areas have been cleared there and these refugees want to go there. I would again humbly submit, let the minister make an equiry about this report that has come out. Also, let him send a team of Members of Parliament to these refugee camps to see the conditions there and make a report and also submit a report about the policy and programme for their rehabilitation.

STATEMENT *RE* : APPOINTMENT BY INDIAN RED CROSS SOCIETY OF OFFICIALS ON A COMMITTEE TO DISTRIBUTE RELIEF MATERIALS

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : श्रीमन, 24 जून,